ISSN:2455-2631 December 2023 IJSDR | Volume 8 Issue 12

# उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में लघु उद्योगों की संभावनाएँ एवं चुनौतियाँ

**डॉ0 राजेश कुमार**
असिस्टेंट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग, अ0प्र0ब0 राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अगस्त्यमुनि (रूद्रप्रयाग), उत्तराखण्ड

**सारांश**

उत्तराखण्ड के पर्वतीय जिले प्राचीन समय से ही प्राकृति संसाधनों, जैव विविधताओं, पारंपरिक हस्तशिल्प तथा कृषि–आधारित उत्पादों से समृद्ध रहे हैं। राज्य गठन से पूर्व पूँजी, आधुनिक तकनीक तथा आधारभूत सुविधाओं के अभाव के कारण इन क्षेत्रों में लघु उद्योंगों का अपेक्षित विकास नहीं हो सका। वर्ष 2000 से पहले इन क्षेत्रों में अधिकतर पारंपरिक उद्योगों का प्रचलन था। इनमें प्रमुख रूप से हथकरघा, हस्तकला, ऊनी वस्त्र, रिंगाल शिल्प, तांबा शिल्प, खादी तथा अन्य अन्य स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्योग शामिल थे।

उत्तराखण्ड राज्य की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है। इन क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुर मात्रा के कारण वन एवं कृषि आधारित उद्योगों के विकास की संभावनाएँ अन्य उद्योगों की अपेक्षा अधिक हैं। ये प्राकृतिक संसाधन इन क्षेत्रों में लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकास के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करते है। यदि इन संसाधनों का वैज्ञानिक एवं योजनाबद्ध ढ़ग से उपयोग किया जाए, तो इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार तथा आय सृजन कर के क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति मिल सकती है। इन क्षेत्रों में लघु तथा कुटीर उद्योगों के सुनियोजित विकास से पर्वतीय क्षेत्रों से होने वाले पलायन की गति को कम किया जा सकता है।

यह शोध पत्र उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में लघु उद्योगों की संभावनाओं और चुनौतियों का विश्लेषण करता है। यह अध्ययन सरकारी रिपोर्टों, शोध लेखों, पुस्तकों और संबंधित प्रकाशनों से एकत्रित द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है।

अध्ययन के निष्कर्षों से पता चलता है कि हस्तशिल्प, हथकरघा उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी फार्मिंग, औषधीय पौधे, मधुमक्खी पालन और इको–टूरिज्म (पारिस्थितिक पर्यटन) पर आधारित उद्योगों में स्थानीय आजीविका को बेहतर बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की काफी क्षमता है। हालांकि, इन उद्योगों के विकास में कई कारक बाधा उत्पन्न करते हैं, जिनमें अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, दुर्गम भूभाग, खराब परिवहन सुविधाएं, बाजारों तक सीमित पहुंच, पूंजी की कमी, आधुनिक तकनीक का अभाव और उद्यमिता कौशल की कमी शामिल हैं। इसके अलावा, प्राकृतिक आपदाएं और पर्यावरणीय संवेदनशीलताएं इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास के समक्ष अतिरिक्त चुनौतियां खड़ी करती हैं।

**महत्वपूर्ण शब्दः** उत्तराखंड, पर्वतीय क्षेत्र, लघु उद्योग, रोजगार सृजन, हस्तशिल्प, पर्यटन, पलायन, चुनौतियाँ और अवसर।

## 1. प्रस्तावना

उत्तराखंड राज्य उत्तर भारत का एक पर्ववतीय राज्य है, जिसकी पहचान समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों, विविध जैव–विविधता, वन संपदा तथा देवभूमि के नाम से होती है। राज्य का यह पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियाँ लघु उद्योगों के विकास के लिए अपार सम्भवनाएं प्रदान करती है जो स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक कौशलों पर आधारित हैं। पर्वतीय क्षेत्रों के आर्थिक विकास कों बढ़ावा देने, रोजगार को सृजित करने, पलायन को रोकने तथा आय स्तर में वृद्धि करने के साथ–साथ क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने में लघु उद्योग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में असमतल भू–भाग, सीमित कृषि भूमि तथा निम्न कृषि उत्पादकता के कारण, केवल कृषि पर अधारित आजीविका ग्रामीण परिवारों के लिए अक्सर स्थायी आजीविका प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं है। परिणामस्वरूप, आर्थिक गतिविधियों में विविधता लाने और रोजगार के वैकल्पिक अवसर पैदा करने के लिए छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में उभरा है। हस्तशिल्प, हथकरघा उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी फार्मिंग, मधुमक्खी पालन, हर्बल उत्पाद और इको–टूरिज्म जैसे उद्योगों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और पर्वतीय क्षेत्रों से होने वाले पलायन को कम करने की काफी क्षमता है।इन अवसरों के बावजूद, पहाड़ी क्षेत्रों में छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इनमें अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा, खराब परिवहन और संचार सुविधाएँ, वित्त तक सीमित पहुँच, आधुनिक तकनीक का अभाव, अपर्याप्त विपणन सहायता और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता शामिल हैं। ये बाधाएँ अक्सर स्थानीय उद्यमों के विस्तार और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में रुकावट डालती हैं।

इस संदर्भ में, प्रस्तुत अध्ययन उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में छोटे पैमाने के उद्योगों की संभावनाओं और चुनौतियों की जाँच करने का प्रयास करता है। यह अध्ययन पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक विकास और स्थायी आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने में सरकारी नीतियों और MSME पहलों की भूमिका का भी अन्वेषण करता है।

## 2. अध्ययन का क्षेत्र

उत्तरी हिमालय प्राचीन काल से ही प्राकृतिक विविध, पारंपरिक स्वदेशी तथा धार्मिक एवं तीर्थ स्थलों के कारण लोगों के लिए प्रेरणा और आकर्षण का प्रमुख स्रोत रहा है।उत्तराखण्ड राज्य मध्य हिमालय के भू–भाग में स्थित है। राज्य की स्थापना 9 नवम्बर, 2000 को हुई थी। प्रशासनिक दृष्टि से राज्य दो मंडलों में विभाजित है, गढ़वाल मंडल में 7 जिले तथा कुमाऊँ मंडल में 6 जिले शामिल हैं। भौगोलिक दृष्टि से यह राज्य 28°43'45" उत्तरी अक्षांश से 31°28'10" उत्तरी अक्षांश तथा 77°35'05" पूर्वी देशांतर से 81°02'25" पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। राज्य का कुल क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 86.07 प्रतिशत भाग पर्वतीय तथा 13.93 प्रतिशत भाग मैदानी है। राज्य के भू–भाग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है, जिसके कारण यहाँ का अधिकांश क्षेत्र पहाड़ी है। पूर्णतः पर्वतीय जिलों में चमोली, रूद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चम्पावत, बागेश्वर तथा अल्मोडा हैं जबकि पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल और नैनीताल में पर्वतीय एवं मैदानी दोनों प्रकार की भौगोलिक एवं सास्कृतिक विशेषताएं विद्यमान हैं। देहरादून, हरिद्वार तथा ऊधमसिंह नगर मैदानी क्षेत्र वाले जनपद हैं। राज्य का मैदानी क्षेत्र दक्षिणी भाग में स्थित है, जो कृषि तथा अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त माना जाता है।

राज्य की इसी भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विविधता के कारण पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए लघु उद्योगों की संभावनाएँ एवं चुनौतियाँ काअध्ययन विशेष महत्व रखता है। पर्वतीय क्षेत्रों का विकास और लघु एवं कुटीर उद्योग दोनों एक–दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। जहाँ लघु एवं कुटीर उद्योगों के अभाव ने पलायन को बढ़ावा दिया है, वहीं प्रभावी नीतियाँ लघु उद्योगों का पलायन को कम करने में सहायक सिद्ध हो सकती हैं।

## 3. साहित्य समीक्षा

**पुरोहित, के0 सी0 (1997)** ने अपने अध्ययन में पाया है कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण राज्य में औद्योगिक विकास अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँच पाया है, जबकि राज्य प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। इसलिए राज्य के लिए यह आवश्यक है कि कि उत्तराखण्ड की भौगोलिक एवं सामाजिक–आर्थिक विशेषताओं को ध्यान में

रखते हुए पृथक औद्योगिक नीति का निर्माण किया जाना चाहिए, जो स्थानीय संसाधनों एवं क्षेत्रीय आवश्यकताओं पर आधारित हो। राज्य में प्राकृतिक संपदा, कृषि, पर्यटन, फलोद्यान, खनिज, पशुधन इत्यादि पर आधारित उद्योगों की अपार संभावनाएं व्याप्त हैं।

**पाण्डेय, डी0 सी0 एवं बिष्ट, पी0 सी0 (2001)** के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन सीमित और बिखरे हुए होते हैं। इसलिए इन परिस्थितियों में बड़े उद्योगों की अपेक्षा लघु उद्योगों का विकास अधिक उपयुक्त माना जा सकता है। इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों में घरेलु तथा लघु उद्योगों को अधिक बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे इन उद्योगों को अपेक्षाकृत कम पूँजी, स्थानीय संसाधनों और पारिवारिक श्रम का उपयोग कर संचालित करने में सुविधा हो सके।

**ममगाई, आर0 एवं रेडडी, डी0 एन0 (2015)**ने अपने अध्ययन में पाया कि उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों के समावेशी विकास हेतु राज्य की नीतिगत रूपरेखा व्यापक एवं सराहनीय है, किन्तु राज्य की औद्योगिक नीतियाँ पर्वतीय क्षेत्रों में अपेक्षित स्तर पर निवेश आकर्षित करने में पूर्णतः सफल नहीं हो सकी हैं।पर्वतीय एवं पिछड़े जिलों में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अधिक संतुलित एवं प्रभावी औद्योगिक विकास नीति की आवश्यकता है।

## 4. अध्ययन के उद्देश्य

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में लघु उद्योगों की संभावनाओं एवं चुनौतियों का अध्ययन करना है। इस अध्ययन के अन्य उद्देश्य निम्न हैं–

1. उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थापित लघु उद्योगों की वर्ततान स्थिति का अध्ययन करना।
2. पर्वतीय क्षेत्रों में लघु उद्योगों के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों का अध्ययन करना।
3. पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति के अनुसार लघु उद्योगों के विकास के लिए नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना।

## 5. लघु उद्योगों की वर्तमान स्थिति

उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के आर्थिक विकास में छोटे पैमाने के उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कृषि योग्य भूमि की कमी, कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण के अभाव के कारण, ये उद्योग स्थानीय आबादी के लिए रोजगार और आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान करते हैं। हस्तशिल्प, हथकरघा, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी फार्मिंग, मधुमक्खी पालन और पर्यटन पर आधारित उद्योग ग्रामीण आजीविका तथा रोजगार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। पिछले कुछ वर्षों में, उत्तराखंड में छोटे पैमाने के उद्योगों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिससे उद्यमिता को बढ़ावा मिला है, पलायन में कमी आई है और संतुलित क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहन मिला है। हालाँकि, अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा, सीमित बाजार पहुँच और वित्तीय बाधाओं जैसी चुनौतियाँ अभी भी इनके विकास और निरंतरता को प्रभावित कर रही हैं।

उत्तराखंड के एक अलग राज्य के रूप में गठन से पहले, प्रदेश में 14,163 स्थायी रूप से पंजीकृत लघु–स्तरीय औद्योगिक इकाइयाँ थीं। इन इकाइयों में लगभग ₹700.29 करोड़ का पूंजी निवेश शामिल किया गया था तथा इन इकाइयों द्वारा 38,509 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया था। यह दर्शाता है कि राज्य बनने से पहले औद्योगिक विकास का स्तर अपेक्षाकृत सीमित था, और रोजगार सृजन में लघु–स्तरीय उद्योगों का योगदान मामूली था।

उत्तराखंड के गठन के बाद, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई औद्योगिक नीतियाँ और विकास योजनाएँ शुरू की गईं। इसके परिणामस्वरूप, मार्च 2022 तक, स्थायी पंजीकरण, उद्यमी ज्ञापन भाग–II, उद्योग आधार और उद्यम पंजीकरण के तहत कुल 73,961 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) पंजीकृत किए जा चुके थे। इन उद्यमों ने

₹15,334.56 करोड़ का पूंजी निवेश आकर्षित किया और 382,431 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए। यह भारी वृद्धि औद्योगिक क्षेत्र में हासिल की गई महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है।

हालाँकि, यह वृद्धि मुख्य रूप से राज्य के मैदानी जिलों में देखी गई है। यद्यपि पहाड़ी जिलों में भी औद्योगिक विकास हुआ है, लेकिन इसकी गति मैदानी क्षेत्रों की तुलना में अपेक्षाकृत धीमी रही है। विभिन्न भौगोलिक और बुनियादी ढाँचे से जुड़ी बाधाओं ने पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योगों के विस्तार को सीमित कर दिया है। उत्तराखंड के पूर्णतः पहाड़ी जिलों में लघु उद्योगों का जिला–वार वितरण निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किया गया है।

**तालिका 2– उत्तराखण्ड के पर्वतीय जनपदों में स्थापित लघु उद्योगों की स्थिति**

| जनपद | दिनांक 8–11–2000 तक (राज्य गठन के समय) स्थापित लघु स्तरीय उद्यम | राज्य गठन के पश्चात् दिनांक 9–11–2000 से माह 31 मार्च, 2022 तक स्थापित उद्यम | कुल स्थापित उद्यम | वृद्धि दर (%) |
|---|---|---|---|---|
| चमोली | 844 | 2901 | 3745 | 243.72% |
| रूद्रप्रयाग | 394 | 2273 | 2667 | 476.90% |
| पिथौरागढ | 534 | 3190 | 3724 | 497.38% |
| चम्पावत, | 147 | 1879 | 2026 | 1178.23% |
| बागेश्वर | 387 | 1838 | 2225 | 374.94% |
| अल्मोडा | 904 | 3945 | 4849 | 336.39% |
| **योग** | **3210** | **16026** | **19236** | **399.25%** |

स्रोत–औद्योगिक विकास विभाग तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग उत्तराखण्ड सरकार वार्षिक प्रतिवेदन 2021–22

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि राज्य बनने के बाद से उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में छोटे पैमाने के उद्योगों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। राज्य बनने के समय, छोटे पैमाने की 3,210 औद्योगिक इकाइयाँ थीं, जो मार्च 2022 तक बढ़कर 16026 हो गईं। यह इस दौरान कुल 399.25 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। जिला–वार विश्लेषण से पता चलता है कि अल्मोड़ा में औद्योगिक इकाइयों की संख्या सबसे अधिक (4,849) रही, जबकि चंपावत में विकास दर सबसे अधिक (1,178.23 प्रतिशत) दर्ज की गई। पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग में भी काफी विकास हुआ। यह विस्तार राज्य बनने के बाद लागू की गई औद्योगिक नीतियों और प्रोत्साहन योजनाओं के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है। हालाँकि, पहाड़ी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को अभी भी भौगोलिक कठिनाइयों, आधारभूत संरचना की कमी तथा सीमित बाजार पहुँच जैसी चुनौतियों से प्रभावित है। अतः इन क्षेत्रों में संतुलित औद्योगिक विकास हेतु विशेष प्रयासों की आवश्यकता है।

**तालिका 2 – उत्तराखण्ड के पर्वतीय जनपदों में स्थापित लघु उद्योगों में रोजगार तथा पूंजी निवेश की स्थिति**

| जनपद | दिनांक 8–11–2000 तक (राज्य गठन के समय) स्थापित लघु स्तरीय उद्यम | | राज्य गठन के पश्चात् दिनांक 9–11–2000 से माह 31 मार्च, 2022 तक स्थापित उद्यम | | कुल स्थापित उद्यमों में रोजगार एवं निवेश | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | रोजगार | पूंजी निवेश (करोड़ रू0 में) | रोजगार | पूंजी निवेश (करोड़ रू0 में) | रोजगार | पूंजी निवेश (करोड़ रू0 में) |
| चमोली | 1154 | 5.45 | 7303 | 123.62 | 8457 | 129.07 |
| रूद्रप्रयाग | 737 | 7.2 | 6581 | 152.15 | 7318 | 159.35 |
| पिथौरागढ | 1013 | 5.85 | 7983 | 126.93 | 8996 | 132.78 |
| चम्पावत, | 322 | 4.95 | 5557 | 97.61 | 5879 | 102.56 |
| बागेश्वर | 607 | 2.04 | 4672 | 84.86 | 5279 | 86.90 |
| अल्मोडा | 1846 | 17.78 | 10251 | 242.21 | 12097 | 259.99 |
| **योग** | **5679** | **4327** | **42347** | **827.38** | **48026** | **870.65** |

स्रोत–औद्योगिक विकास विभाग तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग उत्तराखण्ड सरकार वार्षिक प्रतिवेदन 2021–22

उपरोक्त तालिका से यह साफ पता चलता है कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद, पहाड़ी जिलों में छोटे पैमाने के उद्योगों के जरिए रोजगार पैदा करने और पूंजी निवेश में काफी बढ़ोतरी हुई है। राज्य बनने के समय, इन जिलों में 5,679 लोगों को रोजगार मिला हुआ था, जो मार्च 2022 तक बढ़कर 48,026 हो गया। इसी तरह, कुल पूंजी निवेश भी काफी बढ़कर ₹43.27 करोड़ से ₹870.65 करोड़ हो गया। कुल रोजगार वृद्धि दर **645.68 प्रतिशत** दर्ज की गई, जो इस क्षेत्र में छोटे पैमाने के औद्योगिक क्षेत्र के तेजी से विस्तार का संकेत है।

जनपद–वार विश्लेषण से पता चलता है कि अल्मोड़ा में सबसे अधिक रोजगार पैदा हुआ, जहाँ 12,097 लोगों को नौकरियाँ मिलीं, साथ ही सबसे ज्यादा कुल पूंजी निवेश ₹259.99 करोड़ भी यहीं हुआ। चंपावत में सबसे अधिक रोजगार वृद्धि दर 1,626.40 प्रतिशत दर्ज की गई, जो राज्य बनने के बाद हुए जबरदस्त औद्योगिक विस्तार को दिखाता है। कुल मिलाकर, ये नतीजे बताते हैं कि राज्य बनने के बाद लागू की गई औद्योगिक प्रोत्साहन नीतियों और विकास कार्यक्रमों ने पहाड़ी जिलों में रोजगार के अवसर बढ़ाने और निवेश आकर्षित करने में अहम भूमिका निभाई है। हालाँकि, क्षेत्रीय असमानताएँ अभी भी बनी हुई हैं, जो इन क्षेत्रों में संतुलित औद्योगिक विकास हासिल करने के लिए लगातार नीतिगत सहायता की जरूरत को उजागर करती हैं।

## 6. उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में लघु उद्योगों के समक्ष चुनौतियाँ

### 6.1 बुनियादी ढाँचे की समस्या

उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में लघु उद्योगों के विकास की सबसे बड़ी चुनौती बुनियादी ढाँचे की कमी है। परिवहन और सड़क नेटवर्क कमजोर होने के कारण उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त करने एवं तैयार उत्पादों को बाजार तक पहुँचाने में अनेक कठिनाई होती है। इन जिलों में संकरी एवं घुमावदार सड़कों पर अक्सर भूस्खलन, अतिवृष्टि तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं का असर पड़ता है, जिससे उत्पादन ओर वितरण दोनों प्रभावित होते। इसके अतिरिक्त, विद्युत और

ऊर्जा आपूर्ति भी अस्थिर रहती है, जिसके कारण छोटे उद्योगों को निरंतर उत्पादन बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। नवी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और जल विद्युत की अपार संभावनाएं होने के बावजूद भी इनका उपयोग सीमित रूप में हुआ है। संचार और डिजिटल कनेक्टिविटी की कमी भी एक गंभीर समस्या है। इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क और डिजिटल सेवाओं की सीमित उपलब्धता के कारण उद्यमी ई–मार्केटिंग, ऑनलाइन ऑर्डर, डिजिटल भुगतान और सरकारी योजनाओं की जानकारी का पूरा लाभ नहीं ले पाते।

**6.2 वित्तीय समस्याएं**

पर्वतीय क्षेत्रों में लघु उद्योगों के सामने वित्तीय संसाधनों की कमी एक स्थायी चुनौती है। अधिकांश स्थानीय उद्यमी सीमित पूंजी के साथ काम शुरू करते हैं और उनके पास बड़े निवेश की क्षमता नहीं होती। बैंक ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया जटिल होने के कारण कई छोटे उद्यमी औपचारिक वित्तीय संस्थानों तक आसानी से नहीं पहुँच पाते।गिरवी, दस्तावेज, और बैंकिंग औपचारिकताओं की वजह से ग्रामीण और पर्वतीय उद्यमी अक्सर ऋण लेने से वंचित रह जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप वे अपने उद्योग को आधुनिक मशीनों, पैकेजिंग, भंडारण या विस्तार के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं करा पाते।इसके अतिरिक्त, पर्वतीय क्षेत्रों में जोखिम अधिक है, इसलिए वित्तीय संस्थाएँ भी ऋण देने में सावधानी बरतती हैं। प्राकृतिक आपदा, परिवहन व्यवधान और बाजार अनिश्चितताओं के कारण निवेश की वापसी पर संदेह बना रहता है, जिससे वित्तीय सहायता सीमित हो जाती है।

**6.3 विपणन और प्रचार की कमी**

लघु उद्योगों की एक बड़ी समस्या उनके उत्पादों का सीमित विपणन है। पर्वतीय क्षेत्रों में बनने वाले कई उत्पाद, जैसे मंडुवा, झंगोरा, जड़ी–बूटी उत्पाद, हस्तशिल्प, ऊनी वस्त्र, स्थानीय अचार, जैम और बेकरी उत्पाद, गुणवत्ता में अच्छे होने के बावजूद व्यापक बाजार तक नहीं पहुँच पाते।

प्रचार–प्रसार की कमी के कारण इन उत्पादों की ब्रांड पहचान नहीं बन पाती। उपभोक्ता अक्सर स्थानीय उत्पादों से परिचित नहीं होते, इसलिए उनकी मांग सीमित रहती है। आकर्षक पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मानकीकरण के अभाव में उत्पाद बड़े बाजारों में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते।ई–कॉमर्स और डिजिटल विपणन के साधनों का उपयोग भी सीमित है। यदि स्थानीय उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मेलों, प्रदर्शनियों और सहकारी विपणन नेटवर्क से जोड़ा जाए तो उनकी पहुँच बढ़ सकती है, लेकिन वर्तमान में यह व्यवस्था पर्याप्त नहीं है।

**6.4 प्राकृतिक आपदाएं**

उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र भूस्खलन, बादल फटना, बाढ़, भूकंप और जंगल की आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। इन आपदाओं का सीधा असर लघु उद्योगों पर पड़ता है। सड़कें अवरुद्ध हो जाती हैं, परिवहन बाधित होता है, कच्चे माल की आपूर्ति रुक जाती है और तैयार माल बाजार तक नहीं पहुँच पाता।कई बार उद्योगों की इमारतों, मशीनों और भंडारण इकाइयों को भी नुकसान पहुँचता है। छोटे उद्यमियों के पास आपदा–प्रतिरोधी ढाँचा बनाने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं होती, इसलिए उनका नुकसान अधिक होता है। विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण, कृषि आधारित और वन आधारित उद्योग इन आपदाओं से बहुत प्रभावित होते हैं।बीमा और राहत योजनाएँ उपलब्ध होने के बावजूद पर्वतीय क्षेत्रों में उनका लाभ सीमित स्तर पर ही पहुँचता है। परिणामस्वरूप, उद्यमी जोखिम उठाने से हिचकते हैं और नए उद्योग स्थापित करने में भी संकोच करते हैं।

### 6.5 पलायन की समस्या

पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन एक गहरी सामाजिक–आर्थिक समस्या है। रोजगार के सीमित अवसरों, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी तथा बेहतर जीवन की तलाश में बड़ी संख्या में युवा मैदानी क्षेत्रों या अन्य राज्यों की ओर चले जाते हैं। इसका सीधा प्रभाव लघु उद्योगों पर पड़ता है।जब कुशल और युवा जनशक्ति बाहर चली जाती है, तो स्थानीय उद्योगों को श्रमिक नहीं मिलते। इससे उत्पादन क्षमता घटती है और कई उद्योगों का संचालन कठिन हो जाता है। पलायन के कारण स्थानीय बाजार भी सिकुड़ जाते हैं, क्योंकि उपभोक्ता आधार कम हो जाता है।पारंपरिक उद्योगों, जैसे हथकरघा, हस्तशिल्प और जड़ी–बूटी आधारित कार्यों में अनुभवी कारीगरों की कमी भी पलायन से बढ़ती है। इससे न केवल उद्योग प्रभावित होते हैं, बल्कि क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत पर भी असर पड़ता है।

### 6.6 घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच

पर्वतीय क्षेत्रों के लघु उद्योगों के लिए सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है बाजार तक सीमित पहुँच। स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता अच्छी होने के बावजूद उनके लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जगह बनाना कठिन होता है। इसका कारण परिवहन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मानकीकरण और विपणन नेटवर्क की कमजोरियाँ हैं।अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उपभोक्ता गुणवत्ता, पैकेजिंग और प्रमाणन को बहुत महत्व देते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों के अनेक उत्पाद इन मानकों पर खरे उतर सकते हैं, लेकिन उन्हें उचित प्रमाणन और प्रचार नहीं मिल पाता। इसके कारण वे केवल स्थानीय मेलों या सीमित क्षेत्रीय बाजारों तक ही सीमित रह जाते हैं।यदि उत्पादों को सहकारी विपणन, निर्यात प्रोत्साहन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और पर्यटन से जोड़ा जाए, तो उनकी बाजार पहुँच काफी बढ़ सकती है। लेकिन वर्तमान स्थिति में यह अवसर पूरी तरह उपयोग नहीं हो पा रहा है।

### 6.7 तकनीकी पिछड़ापन

पर्वतीय क्षेत्रों के अधिकांश लघु उद्योग पारंपरिक तकनीकों और पुराने उपकरणों पर आधारित हैं। आधुनिक मशीनरी, स्वचालन, गुणवत्ता परीक्षण, कोल्ड स्टोरेज और डिजिटल प्रबंधन की कमी के कारण उत्पादन की गति और गुणवत्ता सीमित रहती है।

तकनीकी पिछड़ापन उत्पादकता को घटाता है और उत्पादन लागत बढ़ाता है। आधुनिक तकनीक से उत्पादों की गुणवत्ता, पैकेजिंग और बाजार प्रतिस्पर्धा बेहतर हो सकती है, लेकिन इसके लिए प्रशिक्षण और निवेश की आवश्यकता होती है।कई उद्यमियों को नई तकनीक अपनाने की जानकारी नहीं होती, जबकि कुछ के पास इसे खरीदने की वित्तीय क्षमता नहीं होती। परिणामस्वरूप, उद्योग परंपरागत ढाँचे में ही चलते रहते हैं और विस्तार नहीं कर पाते।

### 6.8 कुशल जनशक्ति की कमी

लघु उद्योगों को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित और कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में ऐसे श्रमिकों की कमी रहती है। प्रशिक्षण संस्थानों की सीमित उपलब्धता, रोजगार के लिए बाहर जाने की प्रवृत्ति और तकनीकी शिक्षा का अभाव इस समस्या को बढ़ाते हैं।कुशल जनशक्ति के अभाव में उत्पादन की गुणवत्ता असमान रहती है और उद्योगों की प्रतिस्पर्धा क्षमता कमजोर पड़ती है। कई बार स्थानीय श्रमिक पारंपरिक कार्य तो जानते हैं, लेकिन आधुनिक उत्पादन, पैकेजिंग, विपणन या मशीन संचालन में प्रशिक्षित नहीं होते।यदि स्थानीय युवाओं को कौशल विकास, उद्यमिता प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा दी जाए, तो इस समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

### 6.9 कच्चे माल का प्राप्त न होना

पर्वतीय उद्योगों की एक बड़ी समस्या कच्चे माल की अनिश्चित उपलब्धता है। कई उद्योग वन उत्पादों, कृषि उपज, जड़ी–बूटियों, ऊन, रेशम और स्थानीय फल–सब्जियों पर निर्भर करते हैं। लेकिन मौसम, भौगोलिक कठिनाइयों और परिवहन बाधाओं के कारण कच्चा माल समय पर और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता।

कृषि आधारित उद्योगों में यह समस्या अधिक गंभीर है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में उत्पादन सीमित और मौसमी होता है। फल और सब्जियाँ जल्दी खराब हो जाती हैं, जिससे भंडारण की व्यवस्था न होने पर भारी नुकसान होता है।ऊन, रेशम और वन उत्पादों के लिए भी पर्याप्त आपूर्ति नहीं मिलती, जिसके कारण उद्यमियों को बाहर से कच्चा माल खरीदना पड़ता है। इससे लागत बढ़ती है और उत्पाद महँगे हो जाते हैं।

### 6.10 कार्यशील पूंजी का अभाव

कार्यशील पूंजी लघु उद्योगों के दैनिक संचालन के लिए आवश्यक होती है। इसमें कच्चे माल की खरीद, मजदूरी भुगतान, परिवहन, बिजली, पैकेजिंग और विपणन का खर्च शामिल होता है। पर्वतीय क्षेत्रों के छोटे उद्यमियों के पास अक्सर इतनी पूंजी नहीं होती कि वे नियमित रूप से उत्पादन जारी रख सकें।

बैंक ऋण और सरकारी सहायता योजनाएँ मौजूद होने के बावजूद कार्यशील पूंजी तक आसान पहुँच नहीं है। कई बार भुगतान में देरी, ऋण स्वीकृति की जटिलता और जमानत की अनिवार्यता के कारण उद्यमी उत्पादन को स्थिर नहीं रख पाते।पूंजी की कमी के कारण वे कच्चा माल कम मात्रा में खरीदते हैं, जिससे उत्पादन कम होता है और बाजार में उनकी पकड़ कमजोर पड़ जाती है। यह समस्या उद्योगों के विस्तार को भी रोकती है।

### 6.11 उचित प्रबंधकीय क्षमता का अभाव

पर्वतीय क्षेत्रों में लघु उद्योग अक्सर पारिवारिक या व्यक्तिगत स्तर पर संचालित होते हैं। इन उद्यमियों के पास प्रबंधन, योजना निर्माण, लेखांकन, विपणन और मानव संसाधन प्रबंधन का औपचारिक प्रशिक्षण कम होता है।प्रबंधकीय क्षमता के अभाव में उद्योगों का संचालन व्यवस्थित नहीं हो पाता। कई बार उद्यमी उत्पादन पर ध्यान तो देते हैं, लेकिन बिक्री, लागत नियंत्रण, गुणवत्ता प्रबंधन और विस्तार योजना की ओर कम ध्यान देते हैं।उचित प्रबंधन के बिना उद्योग लंबे समय तक प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते। यदि उद्यमियों को प्रशिक्षण, परामर्श और व्यावसायिक मार्गदर्शन दिया जाए, तो वे अपने उद्योगों को अधिक प्रभावी ढंग से चला सकते हैं।

### 6.12 करारोपण की समस्या

लघु उद्योगों के लिए कर संबंधी जटिलताएँ भी एक बड़ी समस्या हैं। जीएसटी, रिटर्न दाखिल करना, कर अनुपालन और विभिन्न कानूनी औपचारिकताओं को समझना छोटे उद्यमियों के लिए कठिन होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में डिजिटल सुविधाओं की सीमित उपलब्धता इस कठिनाई को और बढ़ा देती है।

कई छोटे उद्यमी कर व्यवस्था की जटिलता से बचने के लिए अनौपचारिक तरीके अपनाते हैं, जिससे वे सरकारी लाभ और योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। कर का बोझ उनके सीमित लाभ को भी प्रभावित करता है।

## 7. पर्वतीय क्षेत्रों में लघु उद्योगों की संभावनाएं

उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में लघु उद्योगों की संभावनाएँ अत्यंत व्यापक हैं, क्योंकि यहाँ पर्यटन, कृषि, बागवानी, जड़ी–बूटी, हस्तशिल्प और महिला उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों के आधार पर उद्योग विकसित किए जा सकते हैं. पर्वतीय भू–भाग की परिस्थितियाँ बड़े उद्योगों की तुलना में छोटे और स्थानीय–आधारित उद्योगों के लिए अधिक अनुकूल मानी जाती हैं।

### 7.1 पर्यटन पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा

उत्तराखंड में पर्यटन लघु उद्योगों के लिए सबसे मजबूत आधारों में से एक है। राज्य में होम–स्टे, गाइड सेवा, ट्रैवल एजेंसी, राफ्टिंग, कैंपिंग, ट्रैकिंग, स्थानीय भोजनालय, स्मृति–उपहार निर्माण और धार्मिक पर्यटन से जुड़े छोटे उद्यम तेजी से विकसित हो सकते हैं. सरकार ने पर्यटन से जुड़े छोटे उद्यमों को वित्तीय प्रोत्साहन देने की दिशा में नई योजनाएँ भी शुरू की हैं, जिससे स्थानीय निवेशकों के लिए यह क्षेत्र और आकर्षक बन गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन आधारित उद्योगों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वे सीधा स्थानीय रोजगार सृजित करते हैं। इससे युवाओं को बाहर जाने के बजाय अपने ही क्षेत्र में काम करने का अवसर मिलता है, जिससे पलायन की समस्या कम हो सकती है. साथ ही, पर्यटन से जुड़े उद्योग स्थानीय उत्पादों की बिक्री को भी बढ़ाते हैं, जैसे ऊनी वस्त्र, हस्तशिल्प, जैविक खाद्य पदार्थ और जड़ी–बूटी उत्पाद।

### 7.2. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

पर्वतीय क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की अपार संभावनाएँ हैं, क्योंकि यहाँ फल, सब्जियाँ, अनाज, दालें और जैविक कृषि उत्पाद अच्छी मात्रा में उपलब्ध हैं। सेब, माल्टा, किवी, मंडुवा, झंगोरा, राजमा और अन्य स्थानीय उत्पादों का प्रसंस्करण कर जैम, जूस, अचार, बेकरी उत्पाद, पैकेज्ड अनाज और रेडी–टू–ईट उत्पाद बनाए जा सकते हैं। खाद्य प्रसंस्करण का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह कृषि उत्पादों को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है और उनकी बर्बादी कम करता है. ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में इस प्रकार के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय योजनाएँ भी उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से बुनियादी ढाँचे, उद्यम औपचारिकीकरण और विस्तार को प्रोत्साहन दिया जा रहा है. पर्वतीय क्षेत्रों के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ परिवहन और भंडारण की कठिनाइयों के कारण कच्चे कृषि उत्पाद जल्दी खराब हो जाते हैं।

### 7.3. महिला उद्यमिता

महिला उद्यमिता पर्वतीय क्षेत्रों के लघु उद्योग विकास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। उत्तराखंड में महिलाओं की भागीदारी पहले से ही घरेलू उत्पाद, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, सिलाई–बुनाई, स्थानीय व्यंजन और होम–स्टे सेवाओं में देखी जाती है. यदि उन्हें प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और विपणन सुविधा मिले, तो वे मजबूत उद्यमी बन सकती हैं। राज्य सरकार ने महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएँ आरंभ की हैं, जिनमें कियोस्क आवंटन, वित्तीय सहायता और पर्यटन क्षेत्रों में व्यवसायिक अवसर शामिल हैं. यह पहल न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करती है, बल्कि परिवारों की आय बढ़ाकर पलायन को रोकने में भी मदद करती है. पर्वतीय क्षेत्रों में महिला उद्यमिता का विस्तार सामुदायिक विकास, स्वावलंबन और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए भी उपयोगी है।

### 7.4. आयुर्वेद एवं जड़ी–बूटी उद्योग

उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र औषधीय पौधों और जड़ी–बूटियों के लिए अत्यंत समृद्ध है। तुलसी, अशलगंधा, जटामांसी, भृंगराज, गुग्गुल, गिलोय, सतावर जैसी अनेक जड़ी–बूटियाँ यहाँ पाई जाती हैं, जिनसे आयुर्वेदिक दवाएँ, स्वास्थ्य उत्पाद और कॉस्मेटिक सामग्री तैयार की जा सकती है.

इस क्षेत्र में लघु उद्योगों की संभावनाएँ इसलिए भी अधिक हैं, क्योंकि जड़ी–बूटी आधारित उत्पादन स्थानीय किसानों, काश्तकारों और वन–आधारित समुदायों के लिए आय का नया स्रोत बन सकता है. यदि इन उत्पादों का वैज्ञानिक ढंग से प्रसंस्करण, पैकेजिंग और ब्रांडिंग की जाए, तो इन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी स्थापित किया जा सकता है. आयुर्वेद और वेलनेस टूरिज्म के साथ जड़ी–बूटी उद्योग का संयोजन पर्वतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत लाभकारी हो

सकता है। योग, आयुर्वेदिक रिसॉर्ट, पंचकर्म केंद्र और हर्बल उत्पादों के सह–उत्पादन से स्थानीय स्तर पर स्थायी रोजगार और नई बाजार संभावनाएँ बन सकती हैं।

**7.5. समग्र महत्व**

पर्वतीय क्षेत्रों में लघु उद्योगों की संभावनाएँ केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक भी हैं। ये उद्योग स्थानीय संसाधनों का मूल्यवर्धन करते हैं, ग्रामीण आजीविका को मजबूत बनाते हैं और परंपरागत ज्ञान को आधुनिक बाजार से जोड़ते हैं.

यदि पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, महिला उद्यमिता और आयुर्वेद–जड़ी–बूटी उद्योगों को उचित नीति, प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और विपणन नेटवर्क से जोड़ा जाए, तो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में लघु उद्योग आत्मनिर्भर विकास का मजबूत आधार बन सकते हैं।

**निष्कर्ष**

उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में लघु उद्योगों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन क्षेत्रों में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन, कृषि उपज, वन संपदा, जड़ी–बूटियाँ, पर्यटन की संभावनाएँ और स्थानीय हस्तकला तथा महिला उद्यमिता जैसे आधार लघु उद्योगों के विकास के लिए मजबूत अवसर प्रदान करते हैं। यदि इन संसाधनों का योजनाबद्ध और वैज्ञानिक ढंग से उपयोग किया जाए, तो पर्वतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिल सकती है।

अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में लघु उद्योग केवल आर्थिक गतिविधि नहीं, बल्कि रोजगार सृजन, पलायन नियंत्रण, ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भरता का प्रभावी माध्यम हैं। विशेष रूप से पर्यटन आधारित उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, आयुर्वेद एवं जड़ी–बूटी उद्योग तथा महिला उद्यमिता जैसे क्षेत्र स्थानीय लोगों के लिए स्थायी आय के स्रोत बन सकते हैं।इसके साथ ही यह भी स्पष्ट है कि इन उद्योगों के विकास के मार्ग में कई गंभीर चुनौतियाँ विद्यमान हैं। बुनियादी ढांचे की कमी, वित्तीय कठिनाइयाँ, तकनीकी पिछड़ापन, कच्चे माल की अनुपलब्धता, विपणन की समस्या, प्राकृतिक आपदाएँ, कुशल जनशक्ति का अभाव तथा करारोपण और प्रबंधकीय कठिनाइयाँ इन उद्योगों की प्रगति को बाधित करती हैं। इन समस्याओं का समाधान किए बिना लघु उद्योग अपनी वास्तविक क्षमता तक नहीं पहुँच सकते।

अतः आवश्यकता इस बात की है कि पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विशेष औद्योगिक नीतियाँ तैयार की जाएँ। सरकार, स्थानीय प्रशासन, बैंकिंग संस्थाएँ और उद्यमी मिलकर यदि प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, तकनीकी उन्नयन, विपणन सुविधा और परिवहन–संचार सुधार की दिशा में कार्य करें, तो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में लघु उद्योग विकास का सशक्त आधार बन सकते हैं। इससे न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि पलायन की समस्या में भी उल्लेखनीय कमी आएगी।

**संदर्भ सूची**

1. एमएसएमई रिपोर्ट (2019–20) – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार।
2. मानव विकास रिपोर्ट (2018) – योजना आयोगध्नीति आयोग द्वारा प्रकाशित।
3. औद्योगिक विकास विभाग तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग उत्तराखण्ड सरकार वार्षिक प्रतिवेदन 2021–22
4. पुरोहित, के0सी0 (1997) 'हमारा उत्तराखंड', बिनसर पब्लिशिंग कं0, पृ0 84.85

5. पाण्डे, डी0सी0 एवं बिष्ट, पी0सी0 (2001) 'पर्वतीय क्षेत्रों में उद्यमिता विकासः सीमाएं तथा संभावनाएं, इकोनॉमी ऑफ उत्तरांचल प्रोफाइल एण्ड डायनमिक ऑफ चेन्ज, अनामिका पब्लिर्स, नई दिल्ली, पृ0 394
6. वार्षिक प्रतिवेदन (2020–21) औद्योगिक विकास विभाग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग उत्तराखण्ड, पृ0 25.116
7. Mamgain, R., Reddy, D.N. (2015). Final report "Outmigration from hill region of Uttarakhand Magnitude, Challenges and Policy Options." National Institutes of Rural Development and Panchayati Raj, Hyderabad, p.23.
8. उत्तराखंड औद्योगिक नीति (2003–2018) – उद्योग विभाग, उत्तराखंड सरकार।
9. एक जनपद दो उत्पाद योजना (2021) – उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में लागू सरकारी योजना।
10. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)– खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार।
11. महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना (2015) – महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
12. आत्मनिर्भर भारत अभियान (2020) – वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।
13. प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) –खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।
14. CIPET (Centre for Skilling and Technical Support), देहरादून – कौशल विकास एवं तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र।
15. उत्तराखंड हर्बल एवं आयुर्वेदिक नीति –आयुष विभाग, उत्तराखंड सरकार।
16. आर्थिक सर्वेक्षण (2020–21) – वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।
17. स्टार्टअप नीति (2018) – उत्तराखंड सरकार द्वारा उद्यमिता प्रोत्साहन हेतु।
18. https://chamoli.gov.in
19. www.doiuk.org.in
20. www.msme.gov.in